फैक्स/सर्वोच्च प्राथमिकता/मा0 न्यायालय प्रकरण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश,

तिलक मार्ग, लखनऊ-226001 ।

संख्या:डीजी-परिपत्र संख्या:74 /2015 दिनाँक:लखनऊ:नवम्बर 8, 2015

सेवा में,

समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद, उ0प्र0।

विषय:-गम्भीर अपराधों(302भा0दं0सं0 इत्यादि) में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने के सम्बन्ध में।

शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या:क्रिमिनल/12425/ इलाहाबाद, दिनांक 28.10.2015(छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया है कि गम्भीर अपराधों(302भा0दं0सं0 इत्यादि) में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्यवाही न होने तथा जानबूझकर प्रकरण को लम्बित रखने एवं नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी न करने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में बहुत अधिक संख्या में रिट याचिकायें योजित की जा रही है।

मा0 न्यायमूर्ति विक्रम नाथ एवं मा0 न्यायमूर्ति ए0एस0 चौहान की संयुक्त पीठ द्वारा विवेचकों द्वारा गम्भीर अपराधों में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी में निष्क्रियता बरतने तथा वरिष्ठ/पर्यवेक्षण अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर अप्रसन्नता व्यक्त की है जो आपराधिक मामलों के विवेचना के पर्यवेक्षण एवं कानून/व्यवस्था के अनुरक्षण के लिए विधिक प्राविधानों से आबद्ध है। इस प्रकार की निष्क्रियता से सम्बन्धित जनपद की कानून/व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है तथा अधिक संख्या में रिट याचिकायें मा0 उच्च न्यायालय में योजित की जा रही है।

अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि मा0 न्यायालय की अपेक्षानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए गम्भीर अपराधों(302भा0दं0सं0 इत्यादि) में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भविष्य में यदि मेरे संज्ञान में यह तथ्य आता है कि गम्भीर अपराधों(302भा0दं0सं0 इत्यादि) में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विवेचक कार्यवाही नही कर रहें है तो विवेचक के साथ पर्यवेक्षण अधिकारी भी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। गम्भीर अपराधों की विवेचना का नियमित रूप से जनपद/परिक्षेत्र/जोन स्तर पर अनुश्रवण किया जायें। इस कार्य में शिथिलता क्षम्य नहीं होगी तथा शिथिलता बरतने वाले विवेचक/प्रभारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी सुनिश्चित की जायें।

संलग्नक:यथोपरि।

8/11/15

(जगमोहन यादव)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्डपीठ को सूचनार्थ प्रेषित।

8-11-15

8/11

OFFICE OF THE GOVERNMENT ADVOCATE, HIGH COURT, ALLAHABAD

Most Urgent / Court Case / Fax – Message

To,

THE DIRECTOR GENERAL OF POLICE,
Uttar Pradesh, Lucknow.

No. Criminal/ 12425 /Allahabad/ Dated: 28.10.2015

Ref: Non apprehending of the named accused in a serious offences like 302 of I.P.C.

::

Dear Sir,

A large number of criminal writ petitions are being filed seeking a writ of mandamus directing the concerned SSP/SP/SHO/SO/IO with regard to inaction of the investigating officer relating to the investigation of the heinous crime i.e. 302 of I.P.C. etc. and sitting tight over the matter and are not taking any action for apprehending the named accused persons for the reason best known to the investigating agency.

The Hon'ble High Court comprising of Hon'ble Mr. Justice Vikram Nath and Hon'ble Mr. Justice A.S. Chauhan has shown their displeasure with regard to the inaction of the investigating officer as well as his senior officers, who are under the statutory obligation to monitor the investigation of criminal cases in question as well as to maintain law and order situation in their respective districts and due to the aforesaid inaction, a large number of litigants are approaching this Hon'ble High Court by filing petition, due to which the Hon'ble High Court is over-burden and has to issue the order / direction pointing out the discharge of their statutory duties of the concerned authorities and as such, the Hon'ble High Court has directed the undersigned to intimate the aforesaid dismay to you and so that you may issue necessary order / direction / circular to all the SSPs/SPs of State of Uttar Pradesh to take immediate steps for apprehending the named accused persons in serious heinous offences unless and until there are reasonable grounds for not taking the aforesaid steps.

The Hon'ble High Court has further directed that after the vacation of Diwali i.e. after 16.11.2015, if any writ petition before this Hon'ble High Court with regard to the aforesaid allegation of inaction of police authority relating to the

heinous offence, the Hon'ble High Court may pass any adverse order, which may cause inconvenience to you as well as State Government.

Kindly look into the matter personally and issue the necessary direction, as stated above, to all the SSPs / SPs of the State of Uttar Pradesh without any delay and a copy of the aforesaid letter shall also be sent to the office of learned Government Advocate, High Court, Allahabad at the earliest, so that this letter alongwith your circular letter be placed before this Hon'ble Court, as and when the same shall be required by the Hon'ble High Court, after the vacation of Diwali i.e. 15.11.2015.

Yours Sincerely,

(A.K. SAND)
Addl. Government Advocate – 1st
High Court, Allahabad
Mb. No. 9415216639